12.00 hrs.

SHORT NOTICE QUESTION

भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की छंटनी

\+

S.N.Q. 4. **श्री बड़े :**
श्री रामसेवक यादव :
श्री यु० द० सिंह :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री सेझियान :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मनोहरन :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री मोहम्मद कोया :
श्री म्र० कु० गोपालन :
श्री कन्डप्पन :
श्री शिवशंकरन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० के० देव :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री बूटा सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामभद्रन :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) क्या भिलाई में पटरी निर्माण संयंत्र बन्द कर दिया है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Iron and Steel (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). No, Sir, it is however a fact that during the last month Bhilai Steel Plant authorities issued notices to 19 Construction Engineers whose contract had expired in December, 1965, as the Construction work relating to Bhilai's expansion Project was tapering off.

(c) No, Sir.

श्री बड़े : यह भिलाई का इस्पात कारखाना जो कि अच्छा चल रहा था वहां मिसमैनेजमेंट और फ़िज़ूलखर्ची होनी शुरू हो गई है और वहां पर नेहरू कलचर हाउस का एक थियेटर बनने जा रहा है जिसका कि उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर साहब करने वाले थे लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि वसा उन्होंने नहीं किया। उसमें ढाई लाख रुपया खर्च होने का एस्टिमेट था लेकिन उसमें कहा गया है कि 12 लाख रुपया और खर्च हो रहा है, 40,000 का फरनीचर दिल्ली से मंगाया गया है। 4000 रुपया मोटर ट्रक का दिल्ली से भिलाई तक ले जाने का किराया दिया गया है इस तरह की फिजूलखर्ची हो रही है उधर 4000 मजदूरों की छंटनी, 123 सुपरवाइजर्स की छंटनी और जो अभी 19 इंजीनियरों की छंटनी की गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की फिजूलखर्ची को कम करके इन लोगों को फिर काम में लगाने की शासन की इच्छा है ?

श्री सेठी : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो रिट्रेंचमेंट का है जो कि यहां पर सामने दरपेश है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स जो कि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले थे वह मेन स्टील वर्क्स में परमानेंट स्टील एम्पलायीज नहीं थे, मुस्तकिल तौर पर वहां नहीं लिये गये हैं, वह कंट्रैक्ट

बेसिस पर लिये गये थे इसलिए उनका जब कंट्रैक्ट समाप्त हो गया तब उनको नोटिसेज़ दे दिये गये हैं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन बहुत सारे लोगों की जिनकी छटनी होने को थी उनमें से बहुत सारे लोगों को काम दे दिया गया है, काफ़ी लोगों को काम देने का प्रयत्न किया गया है और 96 इंजीनियर्स को वापिस काम पर रख दिया गया है और इसी तरह से करीब 6000 वर्कर्स को भिलाई स्टील प्लांट में मेन स्टील प्लांट में काम दिया गया है।

श्री बड़े : मेरे सवाल का जो पार्ट सी० था Whether the rail manufacturing plant at Bhilai is closed, उसका जवाब आना चाहिए। क्या यह बात सच है कि रेल मैनुफैक्चरिंग प्लांट का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि स्टाक फिज़ूल पड़ा हुआ है, इंडियन रेलवेज़ ने उसे लेने से इंकार कर दिया है क्योंकि वह रेल सौफ्ट हैं जबकि मि० आहूजा जो यहां के अफसर हैं जिनको कि 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है उनको प्रवास का 50,000 रुपया सैंक्शन करके अरब देशो में भेजा गया है ताकि वह रेल का मार्केट तलाश करे। हालत यह हो रही है कि जहां पहले तीन पारियां चलती थीं वहां अब एक पारी चलनी शुरू हो गयी है और रेल का स्टाक फिज़ूल पड़ा हुआ है।

श्री सेठी : जहां तक रेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की उत्पादन क्षमता का ताल्लुक़ है उसकी उत्पादन क्षमता 3 लाख 65 हजार टन इस साल की है। अब चूंकि रेलों की डिमांड पहले से कुछ कम हो गई है इसलिए अभी यह कोशिश की जा रही है कि इन रेलों को दूसरे देशों को विदेशों में ऐक्सपोर्ट किया जाए और इसलिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ में मार्केट तलाश करने की कोशिश की जा रही है।

श्री बड़े : उन्होंने लेना नामंजूर कर दिया है क्योंकि हमारे यहां की रेलें सौफ्ट होती हैं।

श्री सेठी : जहां तक क्वालिटी का सवाल है उस में कोई फर्क नहीं है बाक़ी चूंकि उनकी मांग कम हो गई है इसलिए उनका उठाव कम हो गया है और हम उनको बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में आदमी भेजे गये हैं जानकारी लेने के लिए कि कहां उसका एक्सपोर्ट हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : 50,000 रुपया खर्च इसके लिए किया जाना है।

श्री बड़े : मेरे क्वैश्चन के पार्ट सी० का जवाब मंत्री जी ने......

अध्यक्ष महोदय : वह दे दिया है। अब आगे चलने दीजिये।

श्री सेठी : जब कोई बाहर जायगा जितना फारेन एक्सचेंज देना ज़रूरी होगा वह उसे देना होगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जैसा कि माननीय मंत्री ने बतलाया कि उन्होंने कुछ लोगों को काम दिया तो जिनको काम पर उन्होंने रक्खा है वह कितने लोग हैं और वह लोग कितने हैं जिनको कि दूसरे स्थानों पर काम दिया गया है? वहां वह लोग काम नहीं कर सकते हैं, वहां की आबहवा उनको मुआफिक नहीं बैठती डाक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दी है और वह वापिस यहां आ गये हैं लेकिन आज भी उनको काम पर नहीं लिया जाता है तो इसका क्या कारण है? दूसरे जिस समय यह भिलाई स्टील प्लांट बना था उस समय जिन काश्तकारों की ज़मीनें ऐक्वायर की गई थीं उनसे कहा गया था कि हम तुम्हें काम देंगे, काम उन्हें दिया गया लेकिन उसके बाद उन्हें काम से हटाया गया तो उन्हें पुनः काम में लगाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री सेठी : करीब 6200 मजदूरों को मेन स्टील वर्क में काम दिया गया है। उसके अलावा 727 लोगों को दूसरी जगह प्लांट से बाहर काम दिलाने की कोशिश की गई है और उनको काम मिल गया है। 83 लोगों को काम दिलाने के बारे में कोशिश की गई है और उनको काम मिलने वाला है। जितने लोगों की ज़मीनें ली गई थीं और जो कि कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे उनके बारे में यहां से आदेश प्रसारित कर दिया गया है कि यहां चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम समाप्त हो गया है इसलिए जिन लोगों की ज़मीनें ले ली गई हैं उनको मेन स्टील वर्क में स्थान दे दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा प्रश्न दूसरा था। दूसरी जगह जहां भेजा गया था वहां का हवा पानी उनके मुआफिक नहीं था, बौरडर ऐरियाज़ की आबहवा उनके मुआफिक नहीं आयी और डाक्टर की रिपोर्ट है कि वह लोग वहां काम नहीं कर सकते, वे वहां पर डाक्टर की सलाह के अनुसार लौट आये तो उनको यहां काम नहीं दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनको उस स्थान पर काम देने की कोशिश करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वहां काम न हो तो दूसरी जगह देगी। ऐसे कई आदमी थे जो ऐसी दूसरी जगह गये थे और वहां डाक्टर ने कहा कि वह काम नहीं कर सकते और वह वापिस आ गये हैं डाक्टर की सिफारिश पर तो उनको क्या काम में लगाया जायगा ?

श्री सेठी : यदि यहां उनको काम देना संभव होगा तो जरूर इस बात की कोशिश की जायेगी कि उनको काम दिया जाय।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : राज्य सभा में भी यह प्रश्न आया था...

अध्यक्ष महोदय : उसका यहां पर आप हवाला न दें, राज्य सभा में क्या उन्होंने उत्तर दिया उसको आप यहां पर रेफ़र नहीं कर सकते हैं अलबत्ता आप सवाल जो पूछना हो पूछ लीजिये।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों की ज़मीन ली गई थी कारख़ाना बनाते समय क्या उन किसानों को दूसरी जगह भी भूमि दी गई थी या नहीं दी गई...

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह नहीं है है कि भूमि दी गई थी या नहीं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : वह कमायेगें और खायेगें क्या ?

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल दूसरा है। श्री मधु लिमये।

श्री मधु लिमये : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि यह 19 इंजीनियर्स रचना के और निर्माण के काम में थे। इस देश में सरकारी क्षेत्र में निर्माण और रचना का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, आख़िरकार यह जो इंजीनियर लोग हैं, मिस्त्री हैं दूसरे कुशल और निपुण कारीगर होते हैं वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको तालीम देने के लिए समाज बहुत पैसा खर्च करता है, तो जब ऐसे लोगों की छंटनी के कारण यह पैसा फ़िजूल न जाय इसलिए क्या सरकार सारे देश के लिए ऐसे कुशल कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, वैज्ञानिक आदि लोगों का कोई एक पूल बनायेगी ? ताकि अगर इन लोगों का एक योजना में उपयोग नहीं है तो उनको किसी दूसरी योजना में लगाया जा सके वैसे इनकी तालीम पर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है, अनुभव भी पा चुके हैं ये लोग तो उसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : बहुत जगह हमारा काम हो रहा है और उन जाहों पर जहां जहां उन आदमियों की जरूरत पड़ेगी उनको हम लेने की कोशिश करते हैं परन्तु हर काम की सीमा होती

है। यह 19 आदमी जो हैं इनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उसमें समय लगता है। उनको भी तीन महीने का नोटिस है। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही मिनट में सब को नौकरी मिल जाय। उसमें वक्त लगता है। हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सबका कोई एक पूल बनाने की तजवीज़ है?

श्री त्रि० ना० सिंह : कोई ऐसा इंडस्ट्रियल पूल तो नहीं है साइंटिफिक परसनल का एक पूल है और उसमें वे रजिस्टर करा सकते हैं।

श्री मधु लिमये : जवाब क्या हुआ? मैंने कहा था कि जिनको स्किल्ड मेन पावर कहा जाता है .....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो साइंटिफिक लोग हैं उनका पूल है दूसरों का नहीं है।

श्री मधु लिमये : मैंने पूछा था कि क्या उनका विचार है कि इस तरीके के जो निपुण...

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह साइंस वालों के लिये है, दूसरों के लिये नहीं है।

श्री मधु लिमये : यह तो अलग बात हो गई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि ऐसा कोई पूल बनाया जाये।

श्री त्रि० ना० सिंह : इस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। उनका सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Sezhiyan: The Minister said that certain persons had to be retrenched. As per the appointment order, they were given to understand that there was a contract which was likely to be renewed and put on a permanent basis, and also that they would be allowed to work throughout India. In that case I want to know how this retrenchment notice came to be issued on the 14th July and retrenchment took place from 15th July. Was any time allowed to absorb them on some other posts, especially for the senior officers who were working there for ten or fifteen years?

Shri P. C. Sethi: As far as the staff who were working on the onstruction are concerned, they were on a contract basis.

Shri Sezhiyan: Was any indication given to them previously that they would be retrenched? They cannot be retrenched all of a sudden. I want to know whether any indication was given to them that their services would not be required.

Shri P. C. Sethi: They have been given three months' pay.

Shri Sezhiyan: We do not want about pay. Was any indication given to those 19 persons who were retrenched that their services would not be required?

Shri P. C. Sethi: As soon as the work came to a completion, their services would not be required. The contract with the engineers was going to expire on the 31st December, 1965 and this fact was known to them.

Shri Sezhiyan: My question is whether it was intimated to them or whether any indication was given that their services would not be required after a certain date.

Mr. Speaker: He wants to know whether any indication was given to them or not.

Shri T. N. Singh: After the termination of the contract period, it was generally known that their services would not be required. Some people approached me also with regard to continuance because they knew that after the expiry of that period, their services would be terminated. The notice was already there to all of

them that their services would be only for construtcion period. In any case, they were continued as far as possible. In the meantime, we had been trying to find jobs for those people. Even now, there is scope and there are occasions when they may probably get jobs. Beyond that, nothing more can be done.

Shri N. Sreekantan Nair: May I know from the hon. Minister whether last year these people wanted the Bhilai Steel Plant authorities to forward their applications to the Bokaro Steel Plant and they were informed in writing that their services would not be terminated and that they would be allowed to continue in service and if so, whether this retrenchment all of a sudden is not a breach of promise on the part of the Government which is controlling several steel mills in this country and which would ultimately require the services of these people?

Shri T. N. Singh: So far as I know, I was shown a letter which claimed to have given that assurance. I saw that letter. There is no such compulsory assurance or obligatory assurance or a definite assurance that they will be given any jobs.

As far as their employment in Bokaro is concerned, the Managing Director of Bokaro was asked to visit that factory itself—Bhilai—and select as many people from there as he could.

Shri N. Sreekantan Nair: My question was whether their applications were forwarded because the Managing Director of the Bokaro Steel Plant could only interview those people who had sent their applications. My complaint is that these people's applications were not sent on the ground—and they were given this in writing—that they will not be retrenched. Because their applications were not sent, they were not interviewed.

Shri T. N. Singh: There is nothing like that in writing. If the hon. Member can produce any proof, I can look into it. As regards employment in Bokaro, the Managing Director was asked to visit Bhilai and select as many people from there as possible and he did go.

Shri Indrajit Gupta: In view of the fact that these engineers have been retrenched not due to any fault of their own but because the construction work was tapered off, and since the three existing steel plants under the HSL constitute an existing sort of pool where engineers are available, may I know what difficulty the hon. Minister or the HSL feels in recommending the services of these qualified and experienced engineers for absorption in Bokaro where any number of engineers will be required in any case for construction?

Shri T. N. Singh: We are not carrying on much of departmental work at Bokaro....

Shri Sezhiyan: Why?

Shri Indrajit Gupta: They were working under contract in Bhilai also, and not departmentally.

Shri T. N. Singh: Because the construction is not done departmentally there, we have not got large number of engineers required at Bokaro; the work is being done by others and not by the department.

Shri A. K. Gopalan: Did the Bokaro team visit Bhilai and interview these engineers, and if so, were these 19 engineers who were retrenched interviewed by them and offered any appointment at Bokaro and if not, will Government see that that is done?

Shri T. N. Singh: I cannot answer that particular question as to whether they interviewed these 19 engineers or not. I shall have to check up and then say.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: What prevents the Government which controls all these steel mills and which has in view the construction of a huge

mill at Bokaro, from having a kind of pool of their own consisting of all engineers and all kinds of trained personnel? It is not that we have anything like a surplus of trained personnel. What prevents them from forming a pool and getting these people employed there and utilising their services in a planned way? May I know why Government have not formed such a pool and why they are delaying the matter?

Shri T. N. Singh: The pool idea may be looked into, but so far as I see things, I have got great hesitation in doing construction work as a public sector construction work or as a public sector programme, because this is a fluctuating type of work and it varies, tapers off and increases and so on all over the country. I am saying that this is the position as a whole. It is not continuous work. There are certain peak periods when construction work is at its peak; then it tapers off. In the private sector, it is possible to adjust the personnel accordingly, but it is very difficult to do that in the public sector. This is one of the reasons why I am very seriously considering whether we should extend our responsibilities in this matter.

Shri S. Kandappan: On a similar occasion, a few months back, when a question was put about the retrenchment in the Neyveli Lignite Corporation, the hon. Minister had said on the floor of this House that Government were considering the creation of a pool to absorb the surplus engineers and other staff so that people may be drawn from that pool for the exigencies of public sector construction work. We find that even after a lapse of six months, the hon. Minister is giving us the same reply. I do not know what has happened to that consideration. I would like to know whether Government are entitled to mislead the House as they like.

Shri T. N. Singh: I do not know that; I was not the Minister at that time; I shall, however, certainly get it examined.

Mr. Speaker: He might look into it and see whether such a thing was said.

Shri T. N. Singh: I shall certainly look into it.

Shri S. Kandappan: What was the reply to my question?

Mr. Speaker: I have asked him to look into it.

Shri Umanath: The hon. Minister has said that they will not be absorbed in Bokaro because much of the work is going to be given on contract. Even if the work is given on contract, the project authorities will have to employ their own civil engineers. About 200 engineers have been employed in Bhilai to supervise the contract work, which is for about Rs. 10 crores. About Rs. 50 crores worth of contract work is going to be given in Bokaro; so, they will need a larger number of civil engineers under the project authorities. I want to know whether the hon. Minister has considered his question or will consider this question and propose these 19 engineers for Bokaro since they are civil engineers?

Shri T. N. Singh: We have already got the engineering personnel for this purpose. As the hon. Member knows, the Hindustan Construction Ltd. has got a certain minimum number and they go on increasing the number as and when the need arises. But today they are carrying on the work with the number that they have, and they do not need any more; that is what I am told.

Shri Dinen Bhattacharya: Is it a fact that besides these engineers, a large number of skilled and unskilled personnel are being retrenched from the Bhilai steel project, whereas on the other hand the same Bhilai steel plant is recruting new hands? I do not know on what basis these retrenched hands are not getting a chance due to which there has been continuous agitation among the employees of the Bhilai steel plant.

Shri T. N. Singh: Employment and people going out is a continuous process in every factory. I cannot ay what categories are retrenched nd what categories taken in. Unless I know the details, I cannot answer the question.

Shri Dinen Bhattacharya: I have said that many skilled, semi-skilled and unskilled workers are being retrenched.

Shri T. N. Singh: I will look into it.

श्री राम सेवक यादव : 19 इंजीनियरों या सुपरवाइजरों या दूसरे जो निपुण और कुशल लोगों की छंटनी हुई है मैं जानना चाहता हूं कि उनकी छंटनी का आधार क्या था ? उनकी छंटनी मनमाने ढंग से की गई है या उनको उनकी अवधि के हिसाब से निकाला गया है ? यदि ऐसा नहीं है तो क्यों उनको मनमाने ढंग से छांटा गया है ? क्या यह सत्य है कि इनमें जो पुराने थे उनको तो निकाल दिया गया लेकिन जो नए थे उनको रख लिया गया ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कई सौ आदमी इसमें लिये जाते हैं । उनका कांट्रेक्ट पूरा हो गया । उसके बाद कमेटी बनाई गई । उस कमेटी ने देखा उसके बाद जनरल मनेजर ने देखा उसके बाद चैयरमैन स्टील कम्पनी ने रांची में देखा । उन सबके देखने के बाद जो फैसला हुआ वह यह हुआ ।

श्री राम सेवक यादव : यह मेरा प्रश्न नहीं था । यह जानकारी मैंने नहीं मांगी थी । मेरा मतलब यह था कि क्या उनकी सेवा की अवधि को घ्यान में रख कर छांटा गया है ? क्या यह सही है कि उनमें पुराने लोगों को छांटा गया है और नए आदमियों को रख लिया गया है, उनकी छंटनी नहीं की गई है ?

Mr. Speaker: Whether the length of service that one has put in is considered in this connection.

Shri T. N. Singh: I have already said that in the case of these people their contract had terminated. We have to consider what is the requirement of personnel for the minimum work we need to execute. There was no question of last-come-first-to go.

श्री रामसेवक यादव : तभी तो पक्षपात होता है ।

Some hon. Members: Why not.

Shri T. N. Singh: There were a number of people who were employed on contract and their contract had expired. A committee was appointed to look into the matter and see what was the requirement of personnel according to the work on hand. This procedure was adopted.

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी ने कल कहा कि इतना डिसकशन इस सवाल पर हुआ । वह बिलकुल ठीक कहते हैं । मेरे पास इसकी बाबत कई कालिंग एटेंशन नोटिसिस आ चुके हैं । मैंने उनको इसलिए नामंजूर किया था कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन आ रहा है । तभी इतना समय इसको देना पड़ा है ।

श्री त्यागी : मेरी अर्ज यह है कि कोई प्रोपोर्शन इस बात का तय हो जाना चाहिए कि इस किस्म के सवाल पर कितना समय दे सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उसी लिए आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने जो कालिंग एटेंशन नोटिसिस थे उनको नामंजूर इसलिए किया कि यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन आ रहा है । यही वजह है कि मुझे इसमें ज्यादा वक्त देना पड़ा है ।

Shri P. K. Deo: What was the reason for the departure from the pursude policy in regard to the construction programme concerning Bokaro on account of which the work was entrusted to contractors instead of being executed departmentally? Is it due to the fact that this is the pre-election year?

Shri T. N. Singh: This is an old decision. I have also looked into the matter. After experience of things here, I can say that it may not be the

correct thing for the public sector to take on responsibility of this nature where the work involved is of a fluctuating character.

Mr. Speaker: Call attention notice—Shri Kashi Ram Gupta. Ordinarily no Short Notice Question should take more than 10 minutes.

Shri Hari Vishnu Kamath: Ordinarily, we agree.

Mr. Speaker: That is what I said.

Shri Sezhiyan: Even with this time, taken, so many things have not been replied to by the Minister.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pig Iron Complex

*277. **Shrimati Renuka Ray:** Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a pig iron complex is to be set up soon; and

(b) if so, the location and the broad outlines thereof?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): (a) and (b). Decisions regarding the setting up of a pig iron complex will be taken after the Fourth Five-Year programme for iron and steel is finalised.

Report on Steel Controller's Office

*278. **Shri Sidheshwar Prasad:**
Shri Rishang Keishing:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Dr. P. Srinavasan:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Basappa:
Shri Kapur Singh:
Shri Buta Singh:
Shri Gulshan:
Shri Narasimha Reddy:
Shri Rajdeo Singh:
Shri Sinhasan Singh:

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether the Khadilkar Committee has submitted its report on the organisation of the Steel Controller's Office;

(b) if so, the recommendations thereof; and

(c) Government's reactions thereto?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): (a) and (b). Yes, Sir. The Committee has submitted part I of its report dealing with production, distribution and price of indigenous steel. A summary of the recommendations will be found in Chapter VI of the Report which has already been placed on the Table of the House during the last Session of the Parliament.

(c) Recommendations of the Committee are under consideration of the Government.

Manufacture of Scooters

*279. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri Warior:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Yashpal Singh:
Shri H. C. Linga Reddy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri M. R. Krishna:
Shri Rajdeo Singh:
Shri Sinhasan Singh:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of automobiles, particularly of scooters in the country;

(b) if so, the number of new licences issued for the manufacture of scooters during 1966-67 so far; and

(c) when such licences will start the production?

The Minister of Industry (Shri D Sanjivayya): (a) The demand for passenger cars and scooters is in excess of the present production.